

प्रेषक

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संगस्त अधिरासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

विषय अनुषास-1

देहरादून-दिनांक: 19 जनवरी 2010

विषय- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार
षाट् वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु नगरपालिका परिषदों को षतुर्थ
त्रैमासिक की किरत हेतु धनराशि का संकलन।

महोदय

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त
आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये
निर्णयानुसार प्रदेश की 32 नगरपालिका परिषदों को संलग्न विवरण के अनुसार षाट्
वित्तीय वर्ष 2009-10 की षतुर्थ त्रैमासिक की किरत हेतु रु0 177425000.00 (रु0 सत्रह
करोड़ बीहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि संकलित किये जाने की श्री
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकलित की जा रही
है-

(1) संकलित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये वित्त
सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति इस्ताहरित किया जायेगा। संकलित की जा रही धनराशि
का उपयोग शासनादेश सं0-1674/XXVII/(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा
निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का
व्यावर्तन/समायोजन अनुमत्त नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संकलित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा
करने तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि
का आउटर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त
विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से
उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय
अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी
भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो
वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण
सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।


18/1/2010

3- इस सम्बन्ध में होने वाला खय बालू वित्तीय वर्ष 2009-10 की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3804-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेसन -आयोजनेतर-01-नगरीय स्थानीय निकाय-192-नगरपालिका/नगर निकाय-03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संलुत करो से समनुदेसन-00-20- सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्न:- बंधोपरि।

भवदीय
18/1/2010
(एल०एम० पन्त)
सचिव।

संख्या:- 40 (1)/XXVII(1)/2010 तदुदिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मन्त्रालय, गढ़वाल/ कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
- 4- निदेशक शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- समस्त मुख्य/परिषद, कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 8- विभागीय अधिकारी/वित्त निबंधक/मुख्य/परिषद लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
- 9- निजी सचिव, भा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 10- एन० आई०सी० सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
18/1/2010
(एल०एम० पन्त)
सचिव

शासनादेश संख्या: 40 / XXVII (I) / 2010.

दिनांक: 19 जनवरी 2010 का संलग्नक।

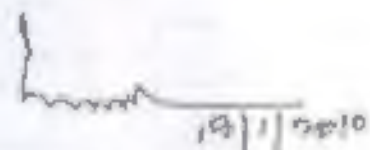
द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत नगर पालिका परिषदों को वर्ष 2009-10 के लिए चतुर्थ किस्त हेतु अवमुक्त संकल्प।

(घनराशि हजार रु० में)

क्र.सं.	स्थानीय निकाय	चतुर्थ किस्त हेतु देय संकल्प
1	2	3
1- नगर पालिका परिषद		
1-	उत्तरकाशी	5854
2-	जोशीमठ	4283
3-	धनोली / गोपेश्वर	5555
4-	नई टिहरी	6418
5-	नरेंद्र नगर	1325
6-	मसूरी	16556
7-	विकासनगर	1583
8-	अधिकेश	7417
9-	दुगडडा	447
10-	कोटद्वार	4895
11-	श्रीनगर	2760
12-	पीडी	8659
13-	टनकपुर	2129
14-	रामनगर	3680
15-	नैनीताल	9158
16-	भवाली	614
17-	हल्द्वानी	15811
18-	जसपुर	3785
19-	काशीपुर	8335
20-	बाजपुर	2010
21-	गदरपुर	1902
22-	रूढ़पुर	13091

क्र.सं.	गाहरी स्थानीय विकास	समुच्चय किरत हेतु र.म. राकम
23-	किच्छा	3128
24-	सितारगंज	2455
25-	खटीमा	2523
26-	रुडकी	8487
27-	मंगलीर	3343
28-	हरिहार	15922
29-	विधीरगढ़	7695
30-	अल्मोडा	4230
31-	बागेश्वर	2050
32-	रुद्रप्रयाग	3525
योग		177425

(रु० सत्रह करोड़ चौहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र)


19/11/2010

(एल०एम० घन्त)
सचिव, वित्त